Revamping of Public Sector Enterprises

1539. SHRI GANESHWAR KUSUM: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have taken steps for revamping the public sector enterprises so that they can improve their performance;

(b) if so, what specific steps have been taken so far in this regard during the financial year 1987-88; and

(c) what would be the overall growth rate of the public sector undertakings during the Seventh Plan period?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) Improvement or revamping wherever warranted is a continuous process in public sector enterprises and the steps taken therefor, have been detailed in pages 182 to - 186 in Chapter-10 of Volume-1 of Public Enterprises Survey 1985-86 laid on the Table of the House in the Budget Session 1987.

(c) In terms of investment the overall annual compound growth rate of the public sector undertakings during the Seventh Plan is about 15 per cent.

Setting up of Oil Refineries by Hindustan Petroleum Corporation Limited

1540. SHRI NARESH C. PUGLIA: Will the Minister of PETROLEUM & NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Hindustan Petroleum Corporation Limited has sought Government's permission to set up two major oil refineries in the next five year plan period;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what are the locations proposed for the setting up of the refineries and what will be the capacity of refining crude by each?

THE MINISTER. OF STATE OF THE, MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) Hindustan Petroleum Corporation Limited has only proposed allocation of funds to undertake Feasibility Studies for two grass root refineries to be set up in the VIII Plan period.

(b) and (c) Schemes to be taken up in the VHIth Plan have not been finalised. Location of oil refineries are decided on various techno-economic considerations and are based on the reports of experts.

पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां

1541. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें पिछले तीन वर्ष के दौरान पेट्रोल पम्प और एल०पी०जी० एजेंसियां दी गई तथा उन बेरोजगार स्नातकों, भूतपूर्व सैनिकों, सामाजिक कार्य-कर्त्ताओं, विधायकों और अन्य व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें उपयुक्त अवधि के दौरान उक्त एजेंसियां दी गईं; और

(ख) क्या ऐसी एजेंसियों का कुछ प्रतिशत आदिवासियों को या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को भी दिया गया है; यदि हां, तो उनकी पृथक-पृथक संख्या कितनी है और यदि ऐसी कोई योजना नहीं है, तो क्या सरकार इस प्रकार की कोई योजना तैयार करने का विचार रखती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी विभिन्न श्रेणियों को आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विवरण क्रमश: अनुबंध-1 [देखिए परिशिष्ट CXLIV, अनुपत्र संख्या 61] और 2 [देखिए परिशिष्ट CXLIV, अनुपत्र संख्या 62] में दिये गये हैं जिनका चयन डीलरशिप

चयन गाइडलाइनों के अनुसार किया जाता है ।

सभी डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिये अनुसूचित जाति और अनूसूचित जन जातियों के लिए 25% का आरक्षण होता है । इन दोनों श्रेणियों के मध्य परस्पर वितरण किसी भी राज्य में दोनों श्रेणियों की आबादी के अनुपात में होता है । पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण का विधान नहीं है ।

पिछड़े वर्ग के लिये अलग से आरक्षण को लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

निर्धन ग्रामीणों को खाना पकाने की गैस की सुविधा प्रदान किया जाना

1542. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस की सुविधा को ग्राम-स्तर पर उपलब्ध कराया जाना अभी शेष है; यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अविलम्ब कोई व्यवस्था करेगी ताकि ग्रामीण महिलायें भी खाना पकाने की गैस की सुविधा का उपयोग कर सकें;

(ख) चालू वर्ष के दौरान भारत के कितने गांवों में खाना पकाने की गैस की सुविधा प्रदान किये जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार इस मामले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कोई भेद रख रही है ;

(घ) क्या यह सच है कि 50 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और इसलिये वे तब तक इस सुविधा का उपयोग नहीं कर पायेंगे जब तक खाना पकाने की गैस के लिये राज-सहायता प्रदान नहीं की जाती; यदि हां, तो क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ङ) क्या बिहार के ग्रामीणों को खाना पकाने की गैस की सुविधा प्रदान करने के लिये अब तक कोई कार्यवाही की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) (ख) और (ङ) तेल उद्योग अपनी विभिन्न विपणन योजनाओं के अधीन 20,000 या इससे अधिक की आबादी (1981 की जनगणना के अनुसार) वाले देश के कस्बों/शहरों को चरणबद्ध रूप में एल० पी०जी० के विपणन के लिये अपने हाथ में ले रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में एल० पी०जी० के विपणन का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) उपर्युक्त (क), (ख) और (ङ) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) घरेलू प्रयोग के लिये एल० पी० जी० पर पहले ही भारी सहायता दी जाती है, इसलिये इस सहायता को बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

LPG Racket in Haryana

1543. SHRI DINKARRAO GOVINDRAO PATH Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether any racket with regard to the supply of LPG has recently been unearthed in Haryana;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) the action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OP THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) and (b) No, Sir. However, a news item captioned "LPG Racket in Haryana" published in the 'Economic Times' of October 20, 1987 has come to notice. This refers